18 लोग घायल हो गए टैंकर की टक्कर के बाद टेंपो ट्रैवलर के खाई में गिरने से। यह हादसा चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर छड़ोल के पास गुरुवार सुबह करीब आठ बजे हुआ।

न्यूज गैलरी

जस्टिस अकील कुरैशी की प्रोन्नति को मिली मंजूरी

नई दिल्ली : बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी के नाम पर कई महीने से जारी गतिरोध खत्म हो गया है। उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किए जाने को हरी झंडी दे दी गई है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने फाइल का निपटारा कर दिया है और अब नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहले जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद कोलेजियम ने अपनी सिफारिश में संशोधन किया और उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। उनकी प्रोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जस्टिस अकील कुरैशी की प्रोन्नति से संबंधित मुद्दे पर 13 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। (प्रेट्र)

चट्टान गिरने से चीन सीमा को जोड़ने वाला हाइवे बंद

चमोली : भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले नीती हाइवे पर भारी-भरकम चट्टान आने से हाइवे दो दिनों से बाधित है। इससे सीमा चौकियों पर जरूरी सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही। हालांकि, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मगर, चट्टान का मलबा अधिक होने और खराब मौसम के चलते हाइवे को खोलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। बता दें कि यह एकमात्र हाइवे है, जिससे भारत-चीन सीमा पर स्थित सेना और आइटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) की चौकियों को रसद समेत अन्य सैन्य सामग्री जाती है। (जासं)

हाई कोर्ट में बहस के बाद वकील गश खाकर गिरा, मौत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस के दौरान एक अधिवक्ता की हृदयगति रुक गई। इससे वह गश खाकर गिर पड़े। वहां मौजूद अधिवक्ता और कर्मचारी उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर के अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोर्ट परिसर में किसी अधिवक्ता की यह पहली मौत है। मूल रूप से सिद्धार्थनगर के निवासी अमूल्य रत्न श्रीवास्तव झूंसी में परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने गुरुवार को हाई कोर्ट में बहस की। बहस के बाद न्यायमूर्ति सलिल राय आदेश लिखने लगे। इसी बीच अमूल्य अचानक गश खाकर गिर गए। इलाज के लिए अमूल्य को पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (जासं)

ऋण वसूली एजेंट ने धमकाया तो दे दी जान

दहिसर (मुंबई) : ऋण वसूली एजेंट ने एक शख्स को इतना धमकाया कि उसने अपनी जान दे दी। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को ऋण वसूली एजेंट के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान अमोल वैती के रूप में की गई है। पुलिस उपायुक्त मोहन कुमार ने बताया कि वैती ने करीब दो माह पहले एक निजी बैंक से ऋण लिया था, लेकिन वह ऋण नहीं चुका सका। इसके बाद ऋण वसूली एजेंट निखिल विश्वकर्मा ने उसे जमकर धमकाया। पुलिस के मुताबिक वैती ने आत्महत्या से पहले अपने परिवार को भेजे मैसेज में एजेंट का नाम और यह कदम उठाने का कारण बताया था। पुलिस ऋण वसूली एजेंट की तलाश कर रही है। (एएनआइ)

जनमत
मुद्दा

क्या आरसेप मुक्त व्यापार समझौते से पीछे हटकर भारत ने अपने बाजार और देसी उत्पादकों के हितों का जरूरी ख्याल रखा है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

दुनिया में मंदी, भारत मजबूती से बढ़ रहा है आगे : मोदी

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ▶ कहा, चार पहियों पर तेजी से चल रहा देश का विकास

हिमाचल पर्यटन से भरपूर, राज्य सरकार ने बनाया निवेश का माहौल

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में मंदी है, लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा। विकास दर में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच भारत ने इज ऑफ डुइंग बिजनेस के मामले में 79वें स्थान पर पहुंचकर सुधार किया है। हर साल संबंधित पैरामीटर के मामले में सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में केंद्र ने 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है, इसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी होगा। भारत में समाज, सरकार, अप्रोच और ज्ञान के चार पहियों विकास की गाड़ी दौड़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों में निवेश के लिए उद्योगपतियों को सरकारें कई तरह की छूट और रियायत देती थीं, लेकिन इस स्थिति में राज्यों को कोई लाभ नहीं हुआ है। देश में निवेश का माहौल बनाना जरूरी है ताकि निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके।

धर्मशाला के पुलिस मैदान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, उद्योगों को गैरजरूरी इंस्पेक्टरी राज से मुक्त करने की जरूरत है और हर स्तर पर सरकारी अनुमति प्रदान करने में तेजी लानी होगी। इस दिशा में अब बदलाव आ रहा है। राज्य सरकारें निवेशकों को उपयुक्त माहौल प्रदान कर रही हैं।

पीएम ने कहा, पिछले कुछ समय में कई तरह के सुधार किए हैं। वैश्विक स्तर पर हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं और राज्यों में स्थानीय जनता लाभान्वित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगपति भी चाहते हैं कि सरकारों में स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली विकसित हो। इस तरह के बदलावों से दूसरे देशों के लिए भारत निवेश करने का फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना है।

100 लाख करोड़ का हिमाचल को भी मिलेगा लाभ

निर्माण क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का जो फैसला लिया है, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल सरकार की ओर से निवेशकों के लिए निवेश का माहौल बनाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। इसके तहत सरकार ने एकल खिड़की से मंजूरी, क्षेत्र विशेष नीतियां जैसे ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, आयुष नीति, उद्योग नीति व भूमि संबंधी धारा 118 का सरलीकरण किया है।

पर्यटन की संभावनाओं का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने धार्मिक, साहसिक, प्राकृतिक और ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं का जिक्र किया।

उप्र में प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट व नाकारा अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) संवर्ग के सात अधिकारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सात पीपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष आयु अथवा उससे अधिक आयु वाले सात पुलिस उपाधीक्षकों/सहायक सेनानायकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

200 से ज्यादा अब तक जबरन रिटायर : राज्य सरकार ने दो वर्षों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों के 200 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की है। अब तक 400 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन व पदावनत करने की कार्रवाई की गई है।

ऊर्जा विभाग में सबसे अधिक कार्रवाई : राज्य सरकार ने दो वर्षों में ऊर्जा विभाग के 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51, ट्रांसपोर्ट विभाग के 37, राजस्व विभाग के 36, बेसिक शिक्षा विभाग के 26, पीडब्ल्यूडी के 18, पंचायतीराज विभाग के 25, श्रम विभाग के 16, संस्थागत वित्त विभाग के 16, कामर्शियल टैक्स के 16, मनोरंजन कर विभाग के 16, ग्राम्य विकास के 15 तथा वन विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

अफगानिस्तान सरकार को भारत ने दी सलाह : 'पानीपत' फिल्म है, फिल्म ही मानें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बॉलीवुड फिल्म 'पानीपत' में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के चरित्र चित्रण पर गुस्सा दिखा रहे अफगानिस्तान सरकार को भारत ने एक अहम सलाह दी है। सलाह यह है कि 'पानीपत' एक फिल्म है और इसे फिल्म के तौर पर ही लें, यथार्थ नहीं मानें। 'पानीपत' को लेकर नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के राजदूत ने सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मिलने का समय मांगा है।

अफगानिस्तानी दूतावास की तरफ से जावडेकर को पत्र लिखकर भारतीय फिल्म में अफगानिस्तानी शासकों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे दोनों देशों के लोगों के बीच मौजूदा भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है।

उधर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बॉलीवुड फिल्म पर ऐतराज जता रहे अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों से कहा है कि, 'वह फिल्म को फिल्म के तौर पर ही लें। अगर बॉलीवुड की फिल्मों को सच्चाई मान कर चलेंगे तो दिक्कत होगी।' सूत्रों की मानें तो अगर अफगानिस्तान दूतावास के अधिकारी मिलने भी आते हैं तो उन्हें यही बात बताई जाएगी कि भारत सरकार का इस फिल्म निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह सेंसर बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में उन्हें जो भी सहयोग चाहिए वह दिया जाएगा।

▶ फिल्म के ट्रेलर से नाराज है अफगानिस्तान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। फाइल

'पानीपत' फिल्म प्रख्यात निर्माता निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने बनाई है जो वर्ष 1791 की मराठा शासकों और अफगानिस्तान के दुर्रानी शासकों के बीच हुए जंग के बारे में है। इसे इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अफगास्तिान के शासक अहमद शाह अब्दाली की भूमिका संजय दत्त ने निभाई है। इसी हफ्ते इसका ट्रेलर जारी किया गया है और जिस दिन इसका ट्रेलर जारी हुआ है उसी दिन से अफगानिस्तान की तरफ से इसमें अब्दाली के चरित्र चित्रण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की मीडिया में यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

ब्लैकमेलिंग के आरोपित भाजपा नेताओं को जारी नहीं हुआ समन

चिन्मयानंद प्रकरण

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- 4700 पेज की केस डायरी व चार्जशीट के पेजों का हुआ मिलान, शनिवार को जारी हो सकता है समन
- डीसीबी चेयरमैन और भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री को भी बनाया गया है आरोपित
- डीपीएस राठौर व अजीत को छोड़ बाकी सभी आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के चेयरमैन व भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डीपीएस राठौर तथा भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह को गुरुवार को कोर्ट से समन जारी नहीं हो सका। मुख्य न्यायिक अधिकारी (सीजेएम) कोर्ट में 4700 पेजों की केस डायरी व बीस-बीस पेजों की दो चार्जशीट के पेजों का मिलान होता रहा। माना जा रहा है कि इस काम के बाद शनिवार को दोनों नेताओं को समन जारी किए जा सकते हैं। डीपीएस राठौर के भाई जेपीएस राठौर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और उन्हें ब्लैकमेलिंग की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) ने की थी। बुधवार को दोनों मुकदमों की चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में दाखिल कर दी गई। एक चार्जशीट में चिन्मयानंद को छात्रा से दुष्कर्म का आरोपित माना गया है। दूसरी चार्जशीट में छात्रा, संजय, विक्रम, सचिन, धर्मेंद्र प्रताप सिंह (डीपीएस) राठौर व अजीत सिंह को चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने का आरोपित माना। डीपीएस राठौर व अजीत को छोड़ बाकी सभी आरोपितों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। चूंकि इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसे में कोर्ट की ओर से समन जारी कर तलब किया जाएगा। तय तारीख कोर्ट में आकर जमानत करानी होगी। चार्जशीट में नाम आने के बाद से डीपीएस राठौर का फोन बंद जा रहा।

मप्र में नेताओं के दुर्व्यवहार से नौकरशाही परेशान, लामबंद होने लगे कर्मचारी संगठन

नईदुनिया, भोपाल

- मंत्री के भतीजे पर विजयपुर जनपद के सीईओ को धमकाने का आरोप, सीईओ संघ हड़ताल पर गया

मध्य प्रदेश में इन दिनों नेताओं व उनके रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार से नौकरशाही परेशान है। मंत्रियों के रिश्तेदार-समर्थक हों या फिर विधायक, मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव ने श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जोशुआ पीटर को न सिर्फ अपशब्द कहे, बल्कि पीटने की धमकी भी दी। घटना के विरोध में सीईओ संघ हड़ताल पर चला गया है। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के रिश्तेदारों ने पोस्टर हटाने को लेकर नगर निगम कर्मियों के साथ मारपीट की।

दमोह जिले के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई प्रजापति ने ट्रेजरी अफसर विवेक कुमार घारू को धमकाया और चेतावनी दी कि वे तबादला करा लें। उधर, भांडेर से कांग्रेस विधायक रक्षा सरोनियां के पति संतराम सरोनियां ने दतिया एसडीएम जेपी गुप्ता से अभद्रता की और उनका मोबाइल छीन लिया।

नेता और उनके समर्थकों द्वारा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की ये कोई नई घटनाएं नहीं हैं। इसके पहले इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय नगर निगम कर्मचारी को बल्ले से पीट चुके हैं। कांग्रेस के रहली विधानसभा से प्रत्याशी कमलेश साहू ने तहसीलदार को धमकाया था। ताजा मामले दो मंत्रियों (लाखन सिंह यादव और तुलसी सिलावट) और विधायकों से जुड़े हैं। इन सभी के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री कमलनाथ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जनप्रतिनिधि अपना व्यवहार शासकीय सेवक और जनता के साथ ठीक रखें। अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। विधायक रामबाई प्रजापति के इसके पहले भी कुछ वीडियो वायरल हो चुके हैं।

असुरक्षा की भावना से घिरे हैं अधिकारी और परिजन : गुप्ता

महासंघ के प्रांताध्यक्ष भूपेश गुप्ता का कहना है कि अधिकारियों के प्रति इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वे और उनके परिजन असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं। हम अपना घर-परिवार छोड़कर प्रदेश की सेवा करने के लिए निकले हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि या कोई अन्य, इस तरह का असम्मानजनक व्यवहार करता है तो यह निंदनीय है। हम सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हैं। वहीं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि नेताओं को अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मामलों में सभी को संयुक्त रूप से खड़े होना चाहिए।

बताया जा रहा है कि लगातार हो रही इन घटनाओं को लेकर अब कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं।

गुजरात में होटल, रेस्तरां के रसोई घर का निरीक्षण कर सकेंगे ग्राहक

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात में अब किसी होटल या रेस्तरां में खाने की कोई शिकायत हो या रसोई घर देखना हो तो ग्राहक उसे देख सकेंगे और इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं का निरीक्षण भी कर सकेंगे। गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर ग्राहकों के हित में यह प्रावधान किया है। गुजरात में पिछले एक महीने में करीब छह प्रतिष्ठित होटलों में ग्राहकों ने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की थी। इसके कारण कई बार ग्राहकों और होटल कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई और थाने में केस हुए। मनपा अधिकारियों ने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड के पिज्जा में कीड़ा मिलने के बाद उसे सील कर दिया था।

गुजरात सरकार ने ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए यह सर्कुलर जारी कर प्रदेश के तमाम महानगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि होटल, कैंटीन और रेस्तरां की रसोई के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हो तो उसे तत्काल हटवाएं और होटल संचालकों से बात कर ग्राहकों को रसोई के अंदर की स्थिति देखने के लिए अलग से दरवाजा लगवाएं। गुजरात सरकार के इस कदम का होटल संचालकों ने स्वागत किया है।

हनीप्रीत मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी हरियाणा पुलिस

जागरण संवाददाता, पंचकूला

पंचकूला हिंसा मामले में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत की राजदार हनीप्रीत पर देशद्रोह की धारा दोबारा लगवाने के लिए पुलिस हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत को दोषी ठहराने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। गत 2 नवंबर को बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के बीच आरोपों पर बहस खत्म होने के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने हनीप्रीत व अन्य को राजद्रोह की धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध की कोशिश) और 121ए (अपराधिक षड्यंत्र) से मुक्त कर दिया था। इसके बाद हनीप्रीत को अंबाला केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद ही हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है। अलग-अलग दस्तावेज देखे जा रहे हैं।

हनीप्रीत। फाइल फोटो

▶ पंचकूला हिंसा मामले में देशद्रोह की धारा जुड़वाने की करेगी कोशिश

पिटीशन फाइल पंचकूला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल को भेज दी गई है जिसमें कई बिंदु डाले गए हैं। उसमें शहर में लगाई गई आग, गाड़ियों को जलाना, सरकारी और निजी भवनों में तोड़फोड़, शहर के हालात को बिगाड़ने आदि जानकारी शामिल हैं। हनीप्रीत की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके लिए पंचकूला में हुए नुकसान, आग, तोड़फोड़, चोट सहित सभी दस्तावेज और गृह मंत्रालय की अप्रूवल भी लगाई जा रही है।

रात को डेरा मुखी की मां के साथ रही हनीप्रीत

25 माह बाद बुधवार रात सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंची हनीप्रीत तेरा आवास के पीछे बनी अपनी कोठी में परिजनों और डेरा प्रमुख की मां नसीब कौर के साथ रही। रात को उसने डेरा समर्थकों से भी मुलाकात की। गुरुवार सुबह उसने कानूनी सलाहकारों और डेरा प्रबंधकों से मुलाकात की। इसके बाद वह डेरा में ही अपने पिता की कोठी में चली गई और दोपहर तक वहां रही।

सरकार दाखिल करे पुनर्विचार याचिका : अंशुल

दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने कहा कि हनीप्रीत सहित अन्य डेरा अनुयायियों पर से देशद्रोह की धारा हटना चिंताजनक है। सरकार को तुरंत पुर्नविचार याचिका दाखिल करनी चाहिए।

विविधता में एकता का दिया संदेश

देश में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, संस्कृति और भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह पूरा देश इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यह हमारी अनूठी विरासत है विविधता में एकता। हरियाणा के पानीपत में गुरुवार को जिलास्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने चेहरे पर तिरंगे के रंग में देश के मानचित्र और धर्मों के प्रतीक की पेंटिंग बनाई। इसके जरिये छात्राओं ने देशवासियों को विभिन्नता में एकता का संदेश दिया और सेल्फी के साथ इस पल को यादों में भी संजो लिया। राजेंद्र फोर

तैयारी

जीएम टीपी सिंह ने बताया, ट्रेन गुजरने से पहले पायलट के पास पहुंचेगी ट्रैक पर अवरोधक की ऑडियो-वीडियो

फाग डिवाइस से लैस होंगे लोको पायलट

जागरण संवाददाता, अंबाला

सर्दियों में धुंध में रेल हादसों से बचने के लिए अब लोको पायलट फाग डिवाइस से लैस होंगे। इस दिशा में रेलवे ने पहले ही तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि धुंध शुरू होने से पहले उत्तर रेलवे के सभी लोको पायलट को यह डिवाइस दे दी जाएगी। यह बात रेलवे के जीएम टीपी सिंह ने कही। वे वीरवार को हिसार से धुरी तक वार्षिक निरीक्षण कर रहे थे। अंबाला कैंट के प्लेटफार्म नंबर दो पर सायं साढ़े 7 बजे जीएम टीपी सिंह रेल सैलून से पहुंचे। उनके साथ डीआरएम दिनेश चंद्र शर्मा भी थे।

प्लेट फार्म दो से वह फुटओवर ब्रिज से सीधे एक नंबर के वीआइपी प्रतीक्षालय में पहुंचे। वेटिंग रूम में वह वार्षिक निरीक्षण के बाबत मीडिया से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अक्टूबर में धुंध का मौसम होता है। इस महीने में रेल संचलन में थोड़ी समस्या देखी जाती है। धुंध के कारण रेल सेवाओं पर कोई असर न पड़े इसके लिए उत्तर रेलवे के सभी लोको पायलट को फाग डिवाइस से लैस किया जाएगा। यदि रेलवे ट्रैक पर किसी तरह का अवरोध रहेगा तो डिवाइस उसकी आडियो और वीडियो ट्रेन गुजरने से पहले लोको पायलट तक पहुंचा देगी। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उकलाना और संगरूर रेलवे कालोनी में जीएम ने पौधरोपण किया। उनके साथ पीसीसीएम मनी आनंद के अलावा राजीव सक्सेना और आरसी ठाकुर सहित अन्य रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रतीकात्मक

छह महीने में 5000 स्टेशन हुए वाईफाई से लैस

जीएम टीपी सिंह ने बताया कि रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशन को वाईफाई से लैस करने की योजना पर काम शुरू किया है। छह महीने में देशभर के पांच हजार रेलवे स्टेशन को वाईफाई सुविधा से लैस किया गया है। स्टेशनों में सीसीटीवी व वाईफाई लगाने का जिम्मा रेलटेक को सौंपा गया है।

रेलवे स्टेशनों पर लगेगी बाटल क्रशिंग मशीन : टीपी सिंह

रेलवे सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण के खतरे को कम करने की कवायद में भी जुटा है। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर बाटल क्रशिंग मशीन लगाने की योजना है। यह मशीन रेलवे स्टेशनों पर जमा होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल अथवा पालीथिन को रिसाइकिल करके ठिकाने लगाने का काम करेगी।

पीएफ घोटाले में एपी मिश्र और सुधांशु द्विवेदी के घर ईओडब्ल्यू का छापा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भविष्य निधि घोटाले में गुरुवार देर शाम एपी मिश्र व सुधांशु द्विवेदी के घरों पर छापा मारा। एपी मिश्र के ऑफिस में भी छानबीन की गई। इससे पहले लखनऊ जेल में बंद आरोपित पावर कॉरपोरेशन पूर्व निदेशक एपी मिश्र, पूर्व निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर दिनभर पूछताछ की। इस दौरान एपी मिश्र ने पीके गुप्ता का सामना करने से इन्कार कर दिया। सवाल यह भी है कि आखिर एपी मिश्र सामने से क्यों बचने का प्रयास कर रहे हैं।

ईओडब्ल्यू ने एपी मिश्र व सुधांशु द्विवेदी को आमने-सामने बैठाकर करीब आधे घंटे तक भविष्य निधि की रकम को निजी कंपनी में निवेश को लेकर सवाल-जवाब किए। सुधांशु व पीके गुप्ता का भी आमना-सामना कराया गया। छापे के दौरान एपी मिश्र के घर व दफ्तर से उनकी एक डायरी, मोबाइल फोन, पैन कार्ड, दो सीपीयू, बैंक पासबुक और और द्विवेदी के घर से लैपटॉप, दो पेनड्राइव व कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए। बता दें 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले की सीबीआइ जांच की संस्तुति भी की जा चुकी है। सीबीआइ जांच शुरू करे, इससे पहले ईओडब्ल्यू पड़ताल में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

▶ पूर्व निदेशक के घर से डायरी व मोबाइल बरामद, एपी मिश्र ने पीके गुप्ता से सामना करने से किया इन्कार

हस्ताक्षर से किया इन्कार : ईओडब्ल्यू की पूछताछ में सुधांशु द्विवेदी ने निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में भविष्य निधि की रकम के निवेश के निर्णय वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने की बात से ही इन्कार कर दिया। ईओडब्ल्यू का कहना है कि डीएचएफएल में निवेश के अप्रूवल संबंधी 2017 की फाइल में एपी मिश्र के हस्ताक्षर हैं। यह अप्रूवल उन्होंने रिटायरमेंट से पहले दिया था।

बयानों से उलझा रहे आरोपित : हालांकि गुरुवार को लंबी पूछताछ के बाद भी अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि 22 मार्च 2017 को हुई बैठक को आखिर 24 मार्च 2017 को होना क्यों दिखाया गया था। इसे लेकर आरोपित अधिकारी बार-बार तारीख याद न होने के बयान दोहराते रहे। पूछताछ के दौरान पीके ने अपने बयानों से डीएचएफएल में निवेश के अप्रूवल को हुई बैठक की कहानी को भी उलझा दिया है। पीके का कहना है कि 22 मार्च 2017 को हुई बैठक केवल कागजों में थी। चूंकि अध्यक्ष ने उस फाइल के कागजात पर दस्तखत के बाद 24 मार्च की तारीख डाली थी, इसलिए 22 को हुई बैठक के दस्तावेजों में तारीख बदली गई। हालांकि वह एपी मिश्र के 23 मार्च 2017 को रिटायर होने के बाद 24 मार्च 2017 की बैठक में शामिल किए जाने के सवाल पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।